जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 वर्षः 20 संख्याः 88 प्रभात जालोर, शनिवार 5 जुलाई, 2025 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

'लंगड़े बारात के घोड़े, ''रेस हॉर्स'' बनना चाहते हैं'

राहुल की इस शिकायत से कई पुराने नेता अति नाखुश, पर बेबस हैं

- रेणु मित्तल -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 4 जुलाई। राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के उन जनरलों (वरिष्ठ नेताओं), जिन्होंने वर्षों तक वफादारी और समर्पण के साथ पार्टी की सेवा की है, के प्रति असभ्य भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें ''लंगड़े घोड़े'' कहा, जो अब बूढ़े, बीमार और संगठन के लिए बेकार हो चुके हैं, जिन्हें अब हटा कर 'चरागाह' में भेज दिया जाना चाहिए। इस पर पार्टी के अंदर जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई।

पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस टिप्पणी से न केवल आहत हैं, बल्कि गुस्से और दुख से भी भर उठे हैं। पार्टी से लंबे समय से जुड़े मझोले स्तर के कार्यकर्ता ने राहुल गांधी की भाषा और शब्दों के चयन को घमंड से भरा तथा एक नेता के लिए अनुपयुक्त करार दिया।

एक अन्य कार्यकर्ता ने यह पूछ लिया कि क्या वे (राहुल) यही शब्द अपनी मां और बहन के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक ने रिटायरमेंट ले लिया है और दूसरी को कुछ वर्षों से कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है।

- पर इतना जरुर हुआ है कि दबी ज़ुबान से सवाल भी पूछे जाने लगे हैं, राहुल गांधी के बारे में।
- जब राहुल, पुराने ''अनफिट'' नेताओं के रिटायरमैंट की बात करते हैं तो सोनिया गांधी का नाम लेने लगे हैं लोग, क्योंकि वे काफी अर्से से बीमार चल रही हैं, पर आखिरी निर्णय में उनकी काफी चलती है।
- जिन लोगों को राहुल रिटायर देखना चाहते हैं, उनमें कमलनाथ, अशोक गहलोत, भूपेन्द्र हुड्डा का नाम ऊपर ही ऊपर है।
- जो, अपने आप रिटायर कर दिये गये उनमें टॉप में नाम है जनार्दन द्विवेदी का, जनार्दन द्विवेदी एक तरह से सोनिया गांधी के ''मैंटर'' जैसे थे, पर, उन्होंने अकारण एक स्टेटमैंट दे दिया कि राजीव गांधी ने उनसे कहा था कि दोनों भाई-बहन में प्रियंका ज्यादा उपयुक्त हैं, राजनीति के लिए। इस वक्तव्य के बाद वो कांग्रेस के रंगमंच से गायब से ही हो गये थे।
- इसी प्रकार गहलोत, हाईकमान के खिलाफ बगावत करने के कारण, ''साइड लाइन्ड'' हैं और लगातार कोशिशों के बावजूद, ''एंट्री'' नहीं पा सके हैं।

जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली है, पार्टी में नेताओं की तीन श्रेणियां उभर कर सामने आई हैं: वे, जिन्हें दरकिनार कर दिया गया है, वे जिन्हें जबरन रिटायर कर दिया गया है, और वे, जो पार्टी के संचालन के तौर-तरीकों से नाखुश होकर पार्टी छोड गये हैं।

सबसे पहला नाम, जिसकी चर्चा पार्टी में होती है, वह है प्रियंका गांधी का। वे हाईकमान का हिस्सा मानी जाती हैं, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें एक तरह से निष्क्रिय कर दिया है। वे कहने को तो एआईसीसी की महासचिव हैं, लेकिन उनके पास न कोई विभाग है, न कोई जिम्मेवारी। उनके करीबी लोग पार्टी पदों से हटा दिए गए हैं और अन्य लोग भी उनसे दूर हो गए हैं, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि प्रियंका उनके करियर में कोई मदद नहीं कर सकतीं।

ऐसे नेताओं की सूची लंबी है। जनार्दन द्विवेदी, जिन्हें सोनिया गांधी का राजनीतिक गुरु तक माना जाता था, ने एक बार सार्वजनिक रूप से कह दिया था कि राजीव गांधी ने उनसे कहा था कि प्रियंका गांधी राजनीति में राहुल से अधिक उपयुक्त हैं तथा वे राजनीति में अच्छा काम कर सकती हैं। उसी दिन से द्विवेदी का पतन शुरू हो गया और वे पूरी तरह हाशिए पर चले गए।

अशोक गहलोत, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं तथा तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'भगवान को न्याय में देखें जजों में नहीं'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत नई दिल्ली-

नई दिल्ली, 4 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को लोगों से यह सलाह दी कि वे भगवान को न्यायाधीशों में न ढूंढ़े बल्कि न्याय में ढूंढ़े। जस्टिस एमएम सुंद्रेश ने यह टिप्पणी उस समय की, जब एक वकील ने कोर्ट में कहा, ''जज हमारे लिए भगवान की तरह होते हैं।'

न्यायमूर्ति सुंद्रेश ने स्पष्ट किया कि न्यायधीश सिर्फ विनम्र सेवक होते हैं और उन्होंने कहा, ''हम में भगवान की न तलाश करें, न्याय में भगवान की तलाश करें। हम केवल विनम्र सेवक हैं।''

- सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुंद्रेश ने एक मामले की सुनवाई के दौरान उस समय यह टिप्पणी की जब वकील ने कहा कि जज हमारे लिए भगवान की तरह होते हैं।

यह टिप्पणी एक वकील द्वारा एक नोटिस पर आपत्ति जताए जाने के बाद आई, जिसमें यह दावा किया गया था कि वकीलों ने न्यायधीशों को फिक्स किया था। वकील ने उस नोटिस को ''अपमानजनक'' बताया।

जस्टिस सुंद्रेश ने कहा, कृपया भावुक न हों। जज के तौर पर हमें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता।''

पिछले साल, भारत के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने भी यह स्पष्ट

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका व भारत के बीच टैरिफ समझौते की सम्भावना लगभग समाप्त

केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वाशिंगटन में पत्रकारों से कहा, भारत ''डैड लाइन'' के दबाव में वाणिज्य समझौते नहीं करता है

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 जुलाई। भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौता, जिसे अमेरिका द्वारा 9 जुलाई से शुरू किए जाने वाले ''रैसिप्रोकल टैरिफ'' से पहले अंतिम रूप दिया जाना था, अब फिलहाल टलता हुआ नजर आ रहा है।

राष्ट्रपति पद के अपने दूसरे कार्यकाल के आरंभ के तुरंत बाद, डॉनल्ड ट्रंप ने विश्व के विभिन्न देशों पर ''रैसिप्रोकल टैरिफ'' लगाने की घोषणा की थी, जिसमें भारत पर भी 25 प्रतिशत शुल्क लगाया गया था, जो 9 जुलाई से लागू होना है।

वॉशिंगटन में केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा पत्रकारों को दिया गया यह बयान, कि भारत किसी डैडलाइन के दबाव में व्यापार समझौते नहीं करता, इस बात का संकेत है कि यह बातचीत अब लम्बे समय तक चल सकती है। भारत यह संदेश देना चाहता था कि उसे दबाव डालकर किसी समझौते के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। भारत सरकार के सर्वोच्च स्तर

- जैसा की विदित ही है, दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रम्प ने घोषणा की थी, कि 9 जुलाई से अमेरिका भारत से आयातित सभी सामान पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगायेगा।
- टैरिफ समझौता वार्ता टूटने का आभास इस बात से भी मिलता है, कि, भारत ने डब्ल्यु.टी.ओ. में कहा है कि अमेरिका द्वारा भारतीय सामान पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा, एक तरफा निर्णय है, और गलत है।
- अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी थी, कि ''रेअर अर्थ'' ख़निज की सप्लाई अमेरिका को तुरन्त शुरू करे अन्यथा कई सख्त आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने पड़ेंगे। इसके बाद चीन ने निर्यात शुरू कर दिया था।
- अमेरिका, भारत से भी यह उम्मीद कर रहा था। पर, पिछले दिनों पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसीफ मुनीर के भड़काऊ भाषणों के बाद पहलगाम नरसंहार हुआ, तथा अमेरिका ने मुनीर को भारी सम्मान दिया उनकी की यात्रा के दौरान।

से स्वीकृति के बिना सार्वजनिक रूप से इस रुख की घोषणा नहीं की जा सकती थी।

इस बीच, भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइज़ेशन के डिस्प्यूट ट्रिब्युनल में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कुंभलगढ़ जिले में मोहर्रम जुलूस की अनुमति का विवाद गहराया

किले में प्रवेश बंद, सैंकड़ों पर्यटक वापस लौटे, बाज़ार पूरा बंद रहा

उदयपुर, 4 जुलाई। (कासं)। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ किले में मोहर्रम के जुलूस की अनुमति को लेकर विवाद अब और अधिक गहराता जा रहा है। शुक्रवार को भी हालात यथावत ही बने रहे। किले में किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, बाजार आज भी बंद रहे और स्थानीय बसों का संचालन भी पूरी तरह ठप्प है। विवाद के कारण बाहर से आने वाले पर्यटक भी किला नहीं देख पा रहे हैं जिससे पर्यटन प्रभावित हुआ है और स्थानीय व्यापारियों में नाराजगी है। हिंदू संघर्ष समिति ने मोहर्रम के जुलूस को दी गई अनुमति को लेकर विरोध जताते हुए आज भी प्रदर्शन किया गया।

समिति का कहना है कि जब पुरातत्व विभाग के नियमों के अनुसार शाम पांच बजे के बाद किले में प्रवेश की अनुमति नहीं होती तो मोहर्रम के ताजियों को शाम को किले में जाने की अनुमति कैसे दी गई। समिति ने इस पर

- हिन्दू संघर्ष समिति का कहना है कि जब पुरातत्व के नियमों के अनुसार, शाम पाँच बजे के बाद किले में प्रवेश की अनुमति नहीं होती तो मोहर्रम के ताजियों को शाम को किले में जाने की अनुमति कैसे दी गई। समिति ने इसे धार्मिक आयोजनों पर दोहरा मापदंड बताया।

कड़ी आपत्ति जताई और धार्मिक आयोजनों में दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। गुरुवार को हिंदू संघर्ष समिति के आव्हान पर बड़ी संख्या में लोग कुंभलगढ़ बस स्टैंड पर एकत्र हुए और किले की ओर मार्च किया। रास्ते में टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन प्रदर्शनकारी आगे बढ़ गए। इस दौरान किले में प्रवेश पर रोक को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में तीखी नोकझोंक भी हुई। संभावित तनाव को देखते हुए प्रशासन ने कुंभलगढ़ में भारी पुलिस बल तैनात किया है।

इस बीच कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड भी प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे विवाद की जड़ पुरातत्व विभाग की गलती है। उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले केलवाड़ा में भी मोहर्रम के रूट को बदला गया था तो यहां भी ऐसा किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन इस मामले में समुचित समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इधर हिंदू संघर्ष समिति ने साफ कर दिया है कि जब तक मोहर्रम जुलूस की अनुमति वापस नहीं ली जाती तब तक कुंभलगढ़ का बाजार अनिश्चितकाल के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कोचिंग विद्यार्थियों की आत्महत्या पर सुनवाई जुलाई के अंत में

जयपुर, 4 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोचिंग सेंटर के विद्यार्थियों के आत्महत्या करने से जुड़े मामले में सुनवाई जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में रखी है। सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस चन्द्र प्रकाश श्रीमाली ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में समान मामला लंबित बताया जा रहा है। वहां 17 जुलाई को

- सुप्रीम कोर्ट का इस बिंदू पर रुख स्पष्ट होने तक हाई कोर्ट ने सुनवाई टाली।

सुनवाई होनी है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उच्च शिक्षा को लेकर मामला सुन रहा है या कोचिंग छात्रों के बिंदु पर प्रकरण की सुनवाई कर रहा है। ऐसे में 17 जुलाई को होने वाली सुनवाई के बाद इसकी स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। इसलिए प्रकरण की सुनवाई जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में करना उचित होगा। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सात हाईकोर्ट्स में 36 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम ने दो दिन तक 54 उम्मीदवारों का इटरव्यू लेकर यह नियुक्तियां की हैं

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 4 जुलाई। न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया में बड़े बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम ने इस सप्ताह की शुरुआत में दो दिन तक 54 उम्मीदवारों के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार किया उसके बाद 7 उच्च न्यायालयों में जजों के रूप में पदोन्नति के लिए रिकॉर्ड 36 नामों को मंज़ूरी दी। इसके साथ ही देशभर के 25 उच्च न्यायालयों में 1,122 स्वीकृत पदों के मुकाबले 371 रिक्तियों में से कुल 90 पद भर दिए गए हैं।

जिन उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए नाम मंज़ूर किए गए हैं, उनमें दिल्ली, पंजाब एवं हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पटना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान सहित कई न्यायालय शामिल हैं।

- इन 36 जजों में से दो जज राजस्थान हाईकोर्ट के लिए चयनित हुए हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा हाईकोर्ट व मध्यप्रदेश में दस-दस, तेलंगाना व गौटारी हाईकोर्ट में 4-4, दिल्ली हाईकोर्ट में तीन तथा पटना हाईकोर्ट में दो जज नियुक्त किए गए है।
- कोलीजियम ने इस बार नियुक्ति के लिए साक्षात्कार का विकल्प चुना है, बजाय दस्तावेजों की जांच के। जिन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हुआ उनमें न्यायिक अधिकारी व वरिष्ठ वकील शामिल हैं।

कोलीजियम के प्रस्ताव के अनुसार, पंजाब एवं हरियाणा और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों में 10-10, तेलंगाना और गुवाहाटी उच्च न्यायालयों में 4-4, दिल्ली उच्च न्यायालय में 3, राजस्थान और पटना उच्च न्यायालयों में 2-2 तथा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 नाम की सिफारिश की गई है।

कोलीजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई, और वरिष्ठ न्यायमूर्ति सूर्यकांत व विक्रम नाथ शामिल हैं। उन्होंने 2 और 3 जुलाई को ये साक्षात्कार आयोजित किए। चयनित उम्मीदवारों में न्यायिक अधिकारी और बार से जुड़े वकीलों का मिश्रण है, जिनका चयन कानूनी समझ, समसामयिक संवैधानिक मुद्दों पर उनके विचार और व्यक्तित्व के व्यापक आकलन के आधार पर किया गया।

कोलीजियम की यह नवीनतम पहल एक स्थायी बदलाव को दर्शाती है, जिसमें केवल दस्तावेज़ी समीक्षा की पारंपरिक प्रणाली से हटकर अब प्रत्यक्ष संवाद और सक्रिय मूल्यांकन पर अधिक जोर दिया जा रहा है। पहले की प्रणाली में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, राज्य सरकारों, केंद्रीय विधि मंत्रालय और खुफिया ब्यूरो की रिपोर्टों को प्रमुखता दी जाती थी, जबकि नई प्रक्रिया में उम्मीदवारों के साथ सीधे संवाद को ज्यादा महत्त्व दिया गया है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि ये साक्षात्कार सुप्रीम कोर्ट की पारंपरिक गर्मी की छुट्टियों के दौरान आयोजित किए गए, जिन्हें अब "आंशिक कार्य दिवस" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस दौरान जहां न्यायिक पीठों ने अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई की, वहीं प्रशासनिक व संस्थागत कार्य, जैसे नियुक्तियाँ आदि, भी सक्रिय रूप से जारी रहे।

सब लैफ्टिनैंट आस्था पूनिया नौ सेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनीं

नयी दिल्ली, 04 जुलाई। सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी हैं।

नौसेना ने शुक्रवार को बताया कि विशाखापत्तनम स्थित नौसैनिक एयर बेस पर दूसरे बेसिक हॉक कन्वर्जन कोर्स के पूरा होने के बाद गुरूवार को उन्हें यह

- बेसिक हॉक कन्वर्ज़न कोर्स के बाद उन्हें यह गौरव मिला। ज्ञातव्य है कि आस्था पूनिया व अतुल कुमार को इस कोर्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए ''विंग्स ऑफ गोल्ड'' सम्मान भी मिला है।

गौरव हासिल हुआ। इस कोर्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए लेफ्टिनेंट अतुल कुमार और सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया को सहायक नौसेना प्रमुख (वायु) रियर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'चीन, पाकिस्तान को ''ऑपरेशन सिंदूर'' के दौरान, भारत के हवाई हमले व सेना के ''मूवमैंट'' की सारी जानकारी तुरंत भेज रहा था'

भारतीय सेना के डिप्टी चीफ, ले.जनरल राहुल आर. सिंह ने स्पष्ट जानकारी दी

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 जुलाई। देश के डेपुटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (कैपेबिलिटी डवलपमैंट एंड सस्टीनेन्स) लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर. सिंह ने आज यह स्वीकार किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को लाइव ऑपरेशनल डेटा प्रदान किया, जिससे भारत की रक्षा और रणनीतिक योजना पर सवाल खड़े हो गए हैं।

भारत की रक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण गैप को उजागर करते हुए, उप सेनाध्यक्ष ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत तीन दुश्मनों से लड़ रहा था। ''हमारे पास एक सीमा थी और दो दुश्मन थे, वास्तव में तो तीन थे। पाकिस्तान तो सामने था। चीन उसे सभी संभव सहायता

- सिंह के अनुसार, उस समय हम तीन दुश्मनों, चीन, पाकिस्तान व टर्की से एक साथ लड़ रहे थे तथा पाकिस्तान का अस्सी प्रतिशत युद्ध का सामान चीन में निर्मित था और चीन द्वारा सप्लाई किया गया था।
- पाकिस्तान, चीन व टर्की यह जानते थे कि जैसे ही युद्ध लंबा खिंचा और उसका स्तर, तकनीकी दृष्टि से और जटिल हुआ, भारत का पलड़ा बहुत भारी हो जाएगा और पाकिस्तान उसके मुकाबले में टिक नहीं पायेगा।
- अतः, जैसे ही युद्ध ''एस्कलेट'' होता दिखा, चीन ने पाकिस्तान को सलाह दी, आत्मसमर्पण करो व संधि की कोशिश करो। इसलिए, पाकिस्तान के डी.जी.एम.ओ. ने भारत के डी.जी.एम.ओ. को फोन किया और युद्ध विराम की अर्ज़ी दी।
- ले.जनरल सिंह के अनुसार, भारत के लिये यह जानना अत्यन्त जरुरी है कि उसके हवाई जहाजों, मिसाइल्स आदि की जानकारी चीन तक कैसे पहुँच रही थी, भारत के सुरक्षातंत्र में इतना बड़ा ''गैप'' क्यों था और कहाँ से आया था।
- ले.जनरल सिंह के अनुसार, भारत ने भी पाकिस्तान की युद्ध विराम की अर्ज़ी इसलिये स्वीकार कर ली, क्योंकि, ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य तो पूरा हो गया था। पाकिस्तान समझ गया था कि भारत अब दर्द बर्दाश्त नहीं करेगा, तुरंत प्रभाव से आंतकवादी हमले का अवश्य जवाब देगा।

प्रदान कर रहा था। पाकिस्तान का 81 प्रतिशत सैन्य हार्डवेयर चीनी है, चीन अपने हथियारों का परीक्षण दूसरे हथियारों के खिलाफ करना चाहता है, तो यह संघर्ष उसके लिए एक ''लाइव'' प्रयोगशाला की तरह था।''

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसी- फिक्की) के एक कार्यक्रम में बोलते हुए, लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने कहा, ''जब डीजीएमओ स्तर की वार्ता चल रही थी, तब पाकिस्तान को चीन से हमारी सैन्य तैनाती के बारे में इनपुट मिल रहे थे। इस मसले पर हमें तेजी से कदम उठाने और उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है, पिछले पांच वर्षों में, पाकिस्तान का 81 प्रतिशत सैन्य हार्डवेयर चीन का ही रहा है।''

सिंह ने कहा कि चीन की मदद से ही पाकिस्तान भारत की गतिविधियों को तुरंत ट्रैक कर सका, जिससे ऑपरेशन का रूप बदल गया और भारत की रक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण झोल (गैप) का पता चला, जिसे जल्दी ही ठीक करने की आवश्यकता है।

सिंह ने यह भी कहा कि तुर्की ने पाकिस्तान को उन्नत किस्म के ड्रोन प्रदान किए। ''तुर्की ने भी पाकिस्तान को विशिष्ट प्रकार का सहयोग देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसने पाकिस्तान को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बिहार के एस.आई.आर. के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस

नयी दिल्ली, 04 जुलाई। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को चुनौती देते हुए इसके खिलाफ वह उच्चतम न्यायालय जायेगी।

कांग्रेस का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया लगभग दो करोड़

- कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के स्पेशल इन्टैंसिव रिवीज़न से दो करोड़ मतदाता वोट देने के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। यह राष्ट्रीय मसला है इसलिए पार्टी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी।

मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की साजिश है।

पार्टी सूत्रों ने आज यहां बताया कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)